



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बरिवार, १८ मार्च, १९९३/२७ फाल्गुन, १९१४

हिमाचल प्रदेश सरकार

गृह विभाग

अधिसूचना

शिमला-१७१००२, १० मार्च, १९९३

संख्या गृह (ए) ए (९)-२४/९३.—राज्य सरकार को सूचना मिली कि बाबा बड़भाग सिंह, मंडी, जिला ऊना में सप्ताह भर चलने वाले मेले में भाग लेने के लिए लाखों श्रदालु आये हुए थे ;

और इस मेले में शुभ घड़ी में पास की नदी में स्नान करने के लिए मध्य राति से ही अपार जन समुदाय एकत्रित होना शुरू हो गया ;

और कि भीड़ में धक्का मुक्की होने के कारण भगदड़ सी मच गई । जिससे करीब १४ श्रदालु भीड़ में कुचल कर मर गए और बहुत सारे घायल हो गये ;

और घटना बहुत महत्वपूर्ण विषय बन गया है ;

और भारत के राष्ट्रपति की यह राय है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए, यह समीचीन होगा कि सार्वजनिक महत्व के कतिपय विशिष्ट मामलों को और उसके कारणों को जानने लिए इस मामले की जांच करवाई जाए ।

अतः भारत के राष्ट्रपति जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुमारी परमिन्द्र हीरा, मण्डलायुक्त, कांगड़ा मण्डल, धर्मशाला को जांच आयोग के रूप में नियुक्त करते हैं;

और इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से एक माह की अवधि के भीतर वह उपरोक्त घटना से सम्बन्धित निम्नलिखित विषयों पर जांच करके अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करने के आदेश देते हैं :—

- (1) तथ्य और परिस्थितियां जिनके कारण यह घटना हुई और उसके क्या कारण थे ;
- (2) जिना प्रशासन ने भीड़ को नियन्त्रित करने के लिए क्या प्रबन्ध कर रखे थे ;
- (3) क्या किसी संस्था अथवा राज्य सरकार से विभाग द्वारा लापरवाही बर्ती गई ? यदि हां तो किससे ?
- (4) भविष्य में ऐसी घटना को रोकने के लिए आवश्यक उपाय ।
- (5) जो अन्य विषय जो जांच अधिकारियों की राय में उपर्युक्त घटना से सम्बन्धित हो ।

राज्यपाल महोदय, इस सम्बन्ध में की जाने वाली जांच की प्रकृति तथा इस मामले को अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह समझते हैं कि जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा (5) की उप-धारा (2), (3), (4) और (5) के उपबन्धों को आयोग के लिए लागू किया जाए और उपरोक्त अधिनियम की धारा की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश देते हैं कि धारा की उप-धारा (2), (3), (4) और (5) में अन्तर्विष्ट उपबन्ध आयोग को लागू होंगे । इस जांच आयोग का मुख्यालय ऊना होगा ।

आदेशानुसार,

एम० एस० मुखर्जी,
मुख्य सचिव,
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

[Authorised Text of notification no. Home (A) A (9)-24/93, dated 10 March, 1993 under Article 345 of the Constitution of India].

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 10th March, 1993

No. HOME (A) A (9)-24/93.—Whereas, it has been reported to the Government of Himachal Pradesh that lacs of devotees converged at Baba Badbhag Singh, Mairi, district Una to attend the week long holy fair there;

And whereas, it has been reported that thousands of people started sitting near the river to have their bath right from the mid of the night;

And whereas, following commotion, the people started running helter and skelter due to which 14 persons were killed in the stampede and some more were injured;

And whereas, this incident has assumed a great public importance;

And whereas, the President of India is of the opinion that it would be more expedient and in public interest to appoint a Commission of Inquiry to enquire into certain specific matters of public importance;

Now, therefore, the President of India in exercise of the powers vested in him under Sub-section (1) of Section 3 of the Commission of Inquiries Act, 1952, is pleased to appoint Miss Parminder Hira, Divisional Commissioner, Kangra at Dharamshala as the Commission of Inquiry and to enquire into and report on the following matters in relation to aforesaid incident, within one month from the date of issue of this notification:—

- (1) Facts and circumstances leading to the incident and the causes thereof;
- (2) What steps had been taken to control movement of people/crowd by the district Administration;
- (3) Was there any lapse on the part of the any organisation or Government Department and if so what ?
- (4) Steps recommended to avoid recurrence of such incidents in future;
- (5) Any other matter which in the opinion of the Commission, is relevant to the incident.

Further, the President of India is of the opinion that having regard to the nature of enquiry to be made and other circumstances of the case, the provisions of sub-section (2), (4) and (5) of section 5 of the Commission of Inquiry Act should be made applicable to the Commission and hereby directs that the said provisions shall apply to the Commission accordingly from the date of issue of this notification. The headquarters of the Commission of Inquiry would be at Una.

By order.

M. S. MUKHERJEE,
Chief Secretary.

